



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. २३१]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त १७, २०१०/श्रावण २६, १९३२

No. २३१]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 2010/SHRAVANA 26, 1932

व्याणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(व्याणिज्य विभाग)  
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, १६ अगस्त, २०१०

**विषय :** कोरिया जन. गण. तथा संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम साइनाइड के आयत के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की निर्णयिक समीक्षा जांच-जांच समाप्त करना

सं. १५/६/२०१०-डीजीएडी.—यतः माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा २००६ की डब्ल्यूपी संख्या १६८९३ में पारित निर्णय के अनुसार पाटनरोधी नियमावली के नियम, २३ के साथ पठित सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, १९९५ की धारा ९क(५) के अंतर्गत, इस बात की जांच करने के लिए कि क्या शुल्क समाप्त कर दिए जाने से पाटन एवं क्षति जारी रहेगी अथवा उनकी पुनरावृत्ति होगी, संबद्ध एसएसआर जांच शुरू की गई थी।

२. और यतः हिंदुस्तान केमिकल्स कम्पनी, जिसे पूर्व में साइनाइट्स एंड केमिकल्स कम्पनी के नाम से जाना जाता था तथा जो मूल जांच तथा प्रथम निर्णयिक समीक्षा में घेरू उद्योग थी, को वर्तमान समीक्षा के संबंध में निर्धारित प्रपत्र एवं पद्धति में संगत सूचना उपलब्ध कराने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था और मामले से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (४० दिनों) की समय-सीमा निर्धारित की गई थी।

३. और यतः उक्त हिंदुस्तान केमिकल्स कम्पनी ने दिनांक २८ जुलाई, २०१० के अपने पत्र द्वारा यह निवेदन किया है कि वे इस समय मामले को आगे जारी रखना नहीं चाहेंगे और वे इस मामले पर इसके आगे जैसा और जब अपेक्षित होगा, पुनर्विचार करेंगे।

3245 GI/2010

४. सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा ९क(५) में यह प्रावधान है कि अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष के समाप्त होने के साथ समाप्त हो जाएगा, बश्ते कि केन्द्रीय सरकार ने एक समीक्षा के माध्यम से यह मत जाहिर किया हो कि इस शुल्क को समाप्त करने पर पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। चूंकि वर्तमान मामले में, ऐसी कोई सूचना रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है जिससे यह निर्धारित किया जा सके वर्तमान शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति की संभावना हो सकती है, अतः प्राधिकारी ने पूर्व में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की अवधि को बढ़ाने हेतु सिफारिश करने पर विचार नहीं किया है। अतः प्राधिकारी दिनांक ९ जून, २०१० की अधिसूचना सं. १५-६-२०१०-डीजीएडी द्वारा शुल्क की गई जांच और इस मामले से संबंधित सभी कार्यवाहियों को एतद्वारा समाप्त करते हैं, और पाटनरोधी शुल्कों को आगे लागू न रखने की सिफारिश करते हैं।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2010

**Subject :** Sunset Review Investigation of Anti-dumping duty on import of Sodium Cyanide originating in or exported from Korea RP and United States of America-Termination of the Investigation

**No. १५/६/२०१०-DGAD.**—Whereas, as per Judgment passed by Hon'ble Delhi High Court in WP No. 16893

of 2006, the subject SSR investigation was initiated under Section 9A(5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 read with Rule 23 of AD Rules, examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury:

2. And whereas Hindustan Chemicals Company, earlier known as Cyanides and Chemicals Company, the domestic industry in the original investigation as well first SSR were requested to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority relating to the present review and were allowed forty days (40 days) from the date of publication of the review notification to submit the information related to the case.

3. And whereas the said Hindustan Chemicals Company vide their communication dated 28th July, 2010 have submitted that they would not like to pursue the case at this stage and would like to revisit the same hereinafter, as and when required.

4. Section 9A(5) of the Customs Tariff Act provides that the anti-dumping duty imposed shall, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In the instant case, since there is no information on record to establish that the cessation of the present duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority does not consider it appropriate to recommend extension of the anti dumping duties earlier imposed. Therefore, the Authority hereby terminates the investigation initiated vide notification No. 15/6/2010-DGAD dated 9th June, 2010, all proceedings connected with this case and recommends that the anti dumping duties need not be extended further.

P.K. CHAUDHERY, Designated Authority